



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 19, 1999/माघ 30, 1920

No. 40]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 19, 1999/MAGHA 30, 1920

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 1999

संख्या 6 (2)/98-डी बी ए-II.—

भारत सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड तथा त्रिपुरा राज्यों में औद्योगिक एककों हेतु कार्यशील पूंजीगत ऋणों पर ब्याज राजसहायता की निम्नलिखित योजना बनाई है :-

1. संक्षिप्त नाम : यह योजना केन्द्रीय ब्याज राजसहायता योजना, 1997 कहलायेगी ।
2. प्रारंभ और अवधि : यह योजना 24 दिसम्बर, 1997 से प्रभावी होगी तथा 31 मार्च, 2007 तक प्रवृत्त रहेगी ।
3. लागू होना : यह योजना नये औद्योगिक एककों अथवा उनके विकास केन्द्रों में पर्याप्त विस्तार अथवा आई आई डी सी अथवा पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्यों द्वारा स्थापित औद्योगिक एस्टेट/पार्क/निर्यात संवर्धन क्षेत्रों तथा इन विकास केन्द्रों से बाहर स्थापित तथा अन्य वर्गीकृत स्थापना स्थलों के विशिष्ट उद्योगों {अनुबंध-क के अनुसार} में नये औद्योगिक एककों अथवा उनके पर्याप्त विस्तार किए जाने के संबंध में लागू रहेगी ।
4. परिभाषाएँ :

{क} "औद्योगिक एकक" से अभिमत है कोई भी औद्योगिक उपक्रम और उपयुक्त सेवा एकक जो भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा विभागीय रूप से चलाये गये एकक से भिन्न है ।

॥ख॥ "नये औद्योगिक एकक" से वह औद्योगिक एकक अभिप्रेत है जिसके बनाये जाने के लिए प्रभावपूर्ण कार्यवाही 24 दिसम्बर, 1997 से पूर्व की गई थी।

॥ग॥ "विद्यमान औद्योगिक एकक" से वह औद्योगिक एकक अभिप्रेत है जिसकी स्थापना योजना की संवादन की तारीख अर्थात् 24 दिसम्बर, 1997 से पूर्व की गई थी।

॥घ॥ "पर्याप्त विस्तार" से क्षमता/आधुनिकीकरण और विविधिकरण प्रयोजनों के लिए किसी औद्योगिक एकक की स्थिर पूंजीनिवेश के मूल्य में 10% से अत्यून की वृद्धि अभिप्रेत है, और

॥ड॥ "प्रभावी उपाय" से निम्नलिखित कार्यवाहियों में से एक या अधिक अभिप्रेत है :-

॥I॥ कि औद्योगिक एकक के लिए जारी पूंजी का 10% अथवा अधिक प्रदत्त किया जा चुका है,

॥II॥ कि फैक्टरी बिल्डिंग का कोई भी हिस्सा निर्मित कर दिया गया है,

॥III॥ कि औद्योगिक एकक के लिए अपेक्षित किसी संयंत्र तथा मशीनरी हेतु निश्चित आर्डर दे दिया गया है।

॥व॥ "स्थिर पूंजी निवेश" से भूमि, बिल्डिंग और संयंत्र तथा मशीनरी में निवेश अभिप्रेत है।

कुल स्थिर पूंजी निवेश का मूल्यांकन निम्नप्रकार से किया जायेगा :-

1॥ भूमि :- संयंत्र के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित सीमा तक भूमि के लिए वास्तविक कीमत की अदायगी, पट्टे पर ली गई भूमि के प्रभार हिसाब में नहीं लिये जायेंगे।

2॥ भवन :- वैसे ही जैसे भूमि के मामले में है। किराये पर लिये गये भवन का किराया हिसाब में नहीं लिया जायेगा।

3॥ संयंत्र एवं मशीनरी :

॥I॥ संयंत्र एवं मशीनरी के मूल्य की गणना करने में स्थापना स्थल पर पूर्ण रूप से स्थापित हो जाने पर संयंत्र एवं मशीनरी की लागत को हिसाब में लिया जायेगा जिसमें टूल, जिग्स, डाइयां तथा मौल्ड्स, परिवहन प्रभार, बीमा प्रीमियम इत्यादि जैसे उत्पादक उपकरणों की लागत भी शामिल होगी।

§11§ कच्चे माल के परिवहन तथा तैयार उत्पादों के विपणन हेतु वास्तविक रूप से उपयुक्त की गई राशि माल को लाने ले जाने में निवेश की गई राशि हिसाब में ली जायेगी ।

§11i§ कच्चे माल तथा अन्य उपभोग्य भंडारों सहित कार्यशील पूंजी को संयंत्र तथा मशीनरी के मूल्य की गणना करते समय शामिल नहीं किया जायेगा ।

§12§ स्थिर पूंजी :- स्थिर पूंजी लेखा वर्ष के अन्तिम दिन को फैक्टरी के स्वामित्वाधीन स्थिर परिसंपत्तियों के ह्रास मूल्य की घोटक है । स्थिर परिसंपत्तियाँ वे हैं जिनकी सामान्य उत्पादकता अवधि एक वर्ष से अधिक की है । स्थिर परिसंपत्तियों में फैक्टरी कार्मिकों के लिए नई अथवा प्रयुक्त अथवा स्वयं निर्मित वे सभी परिसंपत्तियाँ शामिल हैं, जो कि उत्पादन, परिवहन, निर्वाह अथवा मनोरंजन सुविधाओं, अस्पताल, विद्यालय इत्यादि के लिए प्रयुक्त की जाती हैं । इनमें फैक्टरी की आवंटनीय प्रधान कार्यालय की स्थिर परिसंपत्तियाँ शामिल हैं और ब्याज की राशि को छोड़कर किराये खरीद आधार §चाहे वे पूर्णरूपेण अदा किया हो अथवा नहीं§ पर ली गई परिसंपत्तियों का पूर्ण मूल्य भी शामिल है । इसमें अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियाँ और केवल बिजली, भंडारण, वितरण इत्यादि जैसे निर्माणोत्तर कार्यक्रमों के लिए प्रयुक्त परिसंपत्तियाँ शामिल नहीं हैं ।

§13§ वास्तविक कार्यशील पूंजी :- वास्तविक कार्यशील पूंजी की परिभाषा में लेखा वर्ष के अन्तिम दिन फैक्टरी के स्वामित्वाधीन, धारित या नियंत्रित सामग्री, ईंधन और स्नेहक, भण्डार-सामग्री इत्यादि जैसी वे सभी वास्तविक वस्तुएँ शामिल हैं जिनका समावेश फैक्टरी द्वारा स्वतः विनिर्मित उत्पादों में होता है अथवा जिनकी फैक्टरी द्वारा प्रसंस्करण के लिए अन्यो को आपूर्ति की जाती है । वास्तविक कार्यशील पूंजी में केवल पुनः बिजली किए जाने हेतु खरीदी गयी सामग्री, ईंधन और भण्डार-सामग्री आदि का स्टॉक, अर्ध-निर्मित माल और अन्यो के कारण चल रहे कार्य तथा लेखा वर्ष के अंत में बिजली हेतु तैयार की गई फैक्टरी द्वारा विनिर्मित वस्तुएँ भी सीमित हैं । तथापि, इसमें अन्यो द्वारा प्रसंस्करण हेतु फैक्टरी को आपूरित सामान, ईंधन, भण्डार-

सामग्री, आदि का स्टॉक शामिल नहीं किया जाता है। फैक्टरी द्वारा आपूरित कच्चे माल से अन्यो द्वारा प्रसंस्कृत तैयार माल और उनके द्वारा धारित मदों को शामिल किया जाता है और अन्यो द्वारा आपूरित कच्चे माल से फैक्टरी द्वारा प्रसंस्कृत की गयी मदों को शामिल नहीं किया जाता है।

॥१॥ कार्यशील पूंजी : जैसा कि पहले ही अमर परिभाषित किया गया है वास्तविक कार्यशील पूंजी हाथ में और बैंक में नकद जमा राशि और लेखा वर्ष के अंत में देय राशियों पर प्राप्त राशियों के निवल शेष का कुल योग होती है। तथापि, कार्यशील पूंजी में अप्रयुक्त ओवर ड्राफ्ट सुविधा, स्थिर जमा राशियाँ चाहे उनकी अवधि कुछ भी हो, स्थिर परिसंपत्तियों को हासिल करने के लिए अग्रिम, मालिकों और हिस्सेदारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम चाहे उनका प्रयोजन और अवधि कुछ भी हो, ऋण सहित दीर्घावधि ऋण तथा निवेश की राशि, शामिल नहीं है।

5. अनुमत्य राजसहायता की सीमा :-

पूर्वोत्तर क्षेत्र में सभी पात्र औद्योगिक एककों को, अधिसूचित बैंको अथवा केन्द्रीय/राज्य वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान की गई कार्यशील पूंजी पर, उत्पादन शुरू होने की तारीख से अधिकतम 10 {दस} वर्ष की अवधि के लिए 3% तक ऋण राज-सहायता दी जायेगी।

6. कार्यशील पूंजी परिकलन के मापदंड :

इस योजना के प्रयोजनार्थ, एकक की न्यूनतम कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकताओं का उसके वार्षिक कारोबार के 25% की दर पर परिकलन किया जायेगा। उपर्युक्त न्यूनतम स्तर की व्यवस्था करने के उपरान्त, आवश्यकता पड़ने पर, वस्तु-सूची संबंधी मापदंडों को लागू किया जाये। ऐसे एकक जिनके बारे में मापदंड निर्धारित नहीं किये गये हैं / मानदंड लागू नहीं होते हैं {जोकि 10 लाख रुपये की कार्यशील पूंजी की सीमा से नीचे आने वाले एकक हैं}, उनके कार्यशील पूंजी संबंधी अनुरोध पर तब तक अनुग्रहपूर्वक विचार किया जाये जब तक उनकी कार्यशील पूंजी न्यूनतम स्तर के बराबर न हो जाये। वस्तु-सूची और प्राप्तियों के संबंध में विशेष मापदंड भी तैयार किये जा सकते हैं। विशेष परिस्थितियों के तहत जहाँ आवश्यकता प्रत्यक्ष रूप में कम है, न्यूनतम

स्तर से नीचे कार्यशील पूंजी को न्यायोचित माना जाये जैसाकि लघु उद्योग क्षेत्र में सुनिश्चित निदिष्टियों की आपूर्ति और उत्पादन विकास वाले सहायक एककों के मामले में किया जाता है ।

7. राजसहायता के संवितरण हेतु विनिर्दिष्ट एजेंसी :

पूर्वोत्तर विकास वित्तीय निगम {एन ई डी एफ आई} संबंधित राज्य सरकार की सिफारिशों के आधार पर पूंजी निवेश राजसहायता के संवितरण हेतु विनिर्दिष्ट एजेंसी होगी ।

8. ब्याज राजसहायता का दावा प्रस्तुत किए जाने हेतु प्रक्रिया :

उक्त योजना के तहत राजसहायता के लिए पात्र औद्योगिक एकक, नये एककों की स्थापना करने अथवा मौजूदा एककों का पर्याप्त विस्तार करने के लिए प्रभावी कदम उठाने से पूर्व संबंधित राज्य के विभाग में अपने आप को पंजीकृत करवायें और एक एकक के लिए अपेक्षित संभावित कुल कार्यशील पूंजी संबंधी मूल्यांकन का उल्लेख करें । ऐसे एकक, जिन्होंने योजना की घोषणा की तारीख अर्थात् 24.12.97 को अथवा इसके बाद में प्रभावी कदम उठाये है, वे अपने आप को 31.12.1999 तक पंजीकृत करवायेंगे ।

9. ब्याज राजसहायता के संवितरण हेतु प्रक्रिया :

प्रत्येक सम्बद्ध राज्य सरकार प्रत्येक मामले के संबंध में राजसहायता की स्वीकृति और उसकी मात्रा के बारे में अहर्ता पर निर्णय लेने के लिए एक समिति गठित करेगी, जिसमें प्रत्येक संबंधित राज्य विभाग, राज्य वित्त विभाग, राज्य उद्योग निदेशालय, एन.ई.डी.एफ.आई. अथवा इसके विनिर्दिष्ट अभिकरण और संबंधित वित्तीय संस्थान के एक प्रतिनिधि को शामिल किया जाएगा ।

10. एन.ई.डी.एफ.आई. द्वारा एकक को राजसहायता का संवितरण राज्य स्तरीय समिति/ सम्बद्ध राज्य सरकार की सिफारिशों पर किया जाएगा,

11. केन्द्र/राज्य सरकार/वित्तीय संस्थानों के अधिकार :

यदि केन्द्रीय सरकार/संबंधित राज्य सरकार/वित्तीय संस्थान इस बात से संतुष्ट हैं कि किसी औद्योगिक एकक में राजसहायता अथवा अनुदान आवश्यक तथ्यों के बारे में मिथ्याकथन करके, मिथ्या जानकारी प्रस्तुत करके प्राप्त किया है अथवा यदि वह एकक योजना के अंतर्गत राजसहायता का लाभ उठाने के बाद 2 वर्ष की अवधि के अंदर उत्पादन करना बंदकर देता है तो केन्द्र सरकार/संबंधित राज्य सरकार/वित्तीय संस्थान एकक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात अनुदान अथवा राजसहायता वापिस करने के लिए कह सकते हैं ।

12. उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग/संबंधित राज्य सरकार वित्तीय संस्थान का पूर्व में अनुमोदन प्राप्त किये बिना औद्योगिक एकक के किसी भी स्वामी को उक्त औद्योगिक एकक को सम्पूर्ण रूप में अथवा उसके किसी भाग के संस्थापना स्थल को बदलने के लिए या योजना के अंतर्गत संपूर्ण अनुदान अथवा राजसहायता या उसका कोई भाग प्राप्त करने के पश्चात 2 वर्ष की अवधि के अन्दर अपने कुल निर्धारित पूंजी निवेश में पर्याप्त संक्षिप्त अथवा इसके अधिकांश भाग का निपटान करने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

13. अनुदान अथवा राजसहायता प्राप्त करने के बाद प्रत्येक औद्योगिक एकक, उत्पादन प्रारंभ किए जाने के बाद दस वर्ष की अवधि के अपने क्रियाकलापों के बारे में उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग/संबंधित राज्य सरकार को वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

श्रीमती प्रतिभा करन, संयुक्त सचिव

"अनुबन्ध-क"

पूर्वोक्त क्षेत्रों के उचित विकास के लिए कृषि-वन तथा गैस आधारित उद्योगों की अंतरिम सूची :

1. फल तथा सब्जी प्रसंस्करण
 1. डिब्बा बन्द/बोतल उत्पाद
 2. ऐस्पेटिक पैकेज प्रोडक्ट्स
 3. फ्रोजन उत्पाद
 4. निर्जलित उत्पाद
 5. ओलीओरसिन
2. मांस तथा कुक्कुट उत्पाद
 1. मांस उत्पाद {मैंस, भेड़, बकरी तथा सुअर}
 2. कुक्कुट उत्पादन
 3. रेंग पावर प्लांट
3. अनाज आधारित उत्पाद
 1. स्टारच तथा इसके व्युत्पन्नों सहित ज्वार मिलिंग
 2. डबलरोटी, बिस्कुट, नाश्ते के अनाज आदि
4. उपभोग्यता उद्योग
 1. स्नैक
 2. गैर-अल्कोहालिक पेय
 3. चाकलेट सहित मिठाइयाँ
 4. पेस्ता उत्पाद
 5. प्रसंस्कृत सब्जियाँ आदि
 6. प्रसंस्कृत दालें
 7. टेपियन उत्पाद
5. दूध तथा दुग्ध आधारित उत्पाद
 1. दुग्ध पाउडर
 2. पनीर
 3. मक्खन/घी

4. शिशु आहार
5. दूध छुड़ाने वाले आहार
6. माल्टेड युक्त दुग्ध आहार
6. खाद्य पैकेजिंग
7. कागज उत्पाद
8. जूट तथा मेस्टा प्रोडक्ट
9. पशु/मुर्गी/मत्तस्य चारा उत्पादन
10. खाद्य तेल प्रसंस्करण/वनस्पति
11. मौलिक तथा सुगन्धित तेल का प्रसंस्करण
12. प्रसंस्करण तथा बागानों की उपज में वृद्धि :
 1. चाय, रबड़, काफी, नारियल आदि ।
13. गैस आधारित मध्यवर्ती उत्पाद
 1. गैस अन्वेषण तथा उत्पादन
 2. गैस वितरण तथा बोटलिंग
 3. विपुल उत्पादन
 4. प्लास्टिक
 5. रेशे के लिए कच्चा माल
 6. उर्वरक
 7. मेथानोल
 8. फार्मलडीवायसिकल तथा एफ आर रीसिन मैलम तथा एम एफ रेजिन
 9. मिथाइलेशइन, हेक्सा मिथाइलेन टेटराहाइन, अमोनिया बाई कार्बोनेट
 10. नाईट्रिक एसिड तथा अमोनिया नाइट्रेट
 11. कार्बन ब्लैक
 12. पॉलीमर चिप्स
14. कृषि-वन
15. बागवानी

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th February, 1999

No. 6 (2)/98-DBA-II. -- The Government of India is pleased to make the following scheme of Interest Subsidy on the Working Capital Loans for industrial units in the North-Eastern Region comprising the States of Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Tripura with a view to accelerating industrial development in the region.

1. **Short title** : This Scheme may be called the Central Interest Subsidy Scheme, 1997.

2. **Commencement and duration** : It will be effective from the 24th day of December, 1997 and remain in force upto and inclusive of 31.03.2007.

3. **Applicability** : The Scheme is applicable to new industrial units or their substantial expansion in the Growth Centres or IIDCs or industrial estates/parks/export promotion zones set up by States in the North Eastern Region and new industrial units or their substantial expansion in the specified industries (as at Annexure-A) located outside these Growth Centres and other identified locations.

4. Definitions:

- (a) 'Industrial Unit' means any industrial undertaking, suitable servicing unit other than that run departmentally by Government of India/State Government;
- (b) 'New Industrial Unit' means an industrial unit for the setting up of which effective steps were not taken prior to 24th December, 1997;
- (c) 'Existing Industrial Unit' means an industrial unit set-up prior to the operative date of the scheme i.e. 24th December, 1997;
- (d) 'Substantial Expansion' means increase in the value of fixed capital investment of an industrial unit by not less than 10 % for the purpose of expansion of capacity/modernisation and diversification; and
- (e) 'Effective steps' means one or more of the following steps:-
 - (i) that 10% or more of the capital issued for the industrial unit has been paid up;
 - (ii) that any part of the factory building has been constructed;
 - (iii) that a firm order has been placed for any plant and machinery required for the industrial unit.
- (f) 'Fixed Capital Investment' means investment 'in land, building

and plant and machinery.

Total fixed capital investment will be assessed as follows.

- 1) Land: The actual price paid for the land to the extent needed for the purposes of the plant. Charges for the leased land will not be taken into account.
- 2) Building: Same as in the case of land. Rent of a hired building will not be taken into account.
- 3) Plant and machinery:
 - (i) In calculating the value of plant and machinery, the cost of plant and machinery as erected at site will be taken into account which will include the cost of productive equipment, such as tools, jigs, dies and moulds; transport charges, insurance premium, etc. will also be taken into account.
 - (ii) The amount invested on goods carriers to the extent they are actually utilised for transport of raw materials and marketing of the finished products, will be taken into account.
 - (iii) Working capital including raw materials and other consumable stores will be excluded for computing the value of plant and machinery.
- (g) Fixed Capital represents the depreciated value of fixed assets

owned by the factory as on the closing day of the accounting year. Fixed assets are those which have a normal productive life of more than one year. Fixed capital covers all types of assets, new or used or own constructed, deployed for production, transportation, living or recreational facilities, hospitals, schools etc. for factory personnel. It includes the fixed assets of the head office allocable to the factory and the full value of assets taken on hire-purchase by the factory (whether fully paid or not) excluding interest element. It excludes intangible assets and assets solely used for post manufacturing activities such as sale, storage, distribution etc.

- (ii) Physical Working Capital is defined to include all physical inventories owned, held or controlled by the factory as on the closing day of the accounting year such as the materials, fuels and lubricants, stores etc. that enter into products manufactured by the factory itself or supplied by the factory to other for processing. Physical working capital also includes the stock of materials, fuels and stores etc., purchased expressly for re-sale, semi-finished goods and work in progress on account of others and goods made by the factory which are ready for sale at the end of the accounting year. However, it does not include the stock of the materials, fuels, stores, etc. supplied by others to the factory for processing. Finished goods processed by others from raw materials supplied by the factory and held by them are included and finished goods processed by the factory from raw materials supplied by others are excluded.
- (i) Working Capital is the sum total of the physical working capital as already defined above and the cash deposits in hand and at bank and the net balance of amounts receivable over amounts payable

at the end of the accounting year. Working capital, however, excludes unused overdraft facility, fixed deposits irrespective of duration, advances for acquisition of fixed assets, loans and advances by proprietors and partners irrespective of their purpose and duration, long-term loans including interest thereon and investments.

5. Extent of admissible subsidy:

All eligible industrial units in the North Eastern Region shall be given an interest subsidy to the extent of 3% on the Working Capital advanced to them by the Scheduled Banks or Central/State financial institutions for a maximum period of 10 (ten) years from the date of commencement of production.

6. Norms for Working Capital calculation:

For the purpose of this scheme, the minimum working capital requirement of a unit shall be worked out @ 25% of their annual turnover. Inventory norms may be applied, if necessary, after providing for aforesaid minimum level. In respect of such units for which norms have not been laid down/are not applicable (due to the units coming below the cut off point of Rs.10 lakhs of working capital), the request of working capital should be considered favourably so long as the working capital is not very much above such minimum level. Special norms can also be evolved for inventory and receivables. Working capital below the minimum level may be justified under special circumstances in which the requirement is demonstrably lower, as in the case of ancillary units in the small scale sector with assured supply of inputs and off-take of output.

7. Designated Agency for disbursement of Subsidy:

North Eastern Development Financial Corporation (NEDFI) shall be the designated agency for disbursement of interest subsidy on the basis of the recommendation of the concerned State Government.

8. Procedure for claiming Interest Subsidy:

Industrial units eligible for subsidy under the scheme will get themselves registered with the State Department concerned prior to taking effective steps for setting up the new units or undertaking substantial expansion of the existing units and indicate their assessment of the total working capital likely to be required for a unit. Such of the units as had taken effective steps on or after 24.12.1997 i.e. the date of announcement of the scheme will get themselves registered by 31.12.1999.

9. Procedure for disbursement of Interest Subsidy:

Each State Government concerned will set up a State Level Committee consisting of a representative each of the State Department concerned, the State Finance Department, State Directorate of Industries, NEDFI or its designated agency and the financial institution concerned, to go into each case to decide whether it qualifies for the grant of subsidy and also about the quantum of subsidy.

10. The subsidy will be disbursed to the unit by NEDFI on the recommendation of the State Level Committee/State Government concerned.

11. Rights of the Centre/State Government/Financial Institutions:

If the Central Government/State Government/financial Institution concerned is satisfied that the subsidy or grant to an industrial unit has been obtained by misrepresentation of the essential facts, furnishing of false information or if the unit goes out of production within 2 years after having availed the subsidy under the scheme, the Central Government/State Government/Financial Institution concerned may ask the unit to refund the grant or subsidy after giving opportunity to the concerned to be heard.

12. Without taking prior approval of the Ministry of Industry, Department of Industrial Policy & Promotion/State Government/Financial Institution concerned, no owner of an industrial unit will be allowed to change the location of the whole or any part of the industrial unit or effect any substantial contraction or disposal of a substantial part of its total fixed capital investment within a period of 2 years of receiving a part or the whole of the grant or subsidy under the scheme.

13. After receiving the grant of subsidy, each industrial unit shall submit annual progress report to the Ministry of Industry, Department of Industrial Policy and Promotion/State Government concerned, about its working for a period of 10 years after going into production.

SMT. PRATIBHA KARAN, Jt. Secy.

ANNEX—A

Tentative List of Agro-Forest and Gas-based Industries Appropriate for Development in the North Eastern Regions**1. Fruit and Vegetable Processing**

- (i) Canned/Bottled Products
- (ii) Aseptic Packaged Products
- (iii) Frozen Products
- (iv) Dehydrated Products
- (v) Oleoresins

2. Meat and Poultry Products

- (i) Meat Products (buffalo, sheep, goat and pork)
- (ii) Poultry Production
- (iii) Egg Power Plant

3. Cereal Based Products

- (i) Maize Milling including starch and its derivatives
- (ii) Bread Biscuits, Break fast Cereals etc.

4. Consumer Industry

- (i) Snacks
- (ii) Non-Alcoholic Beverages
- (iii) Confectionery including Chocolate
- (iv) Pasta Products
- (v) Processed Spices etc.
- (vi) Processed Pulses
- (vii) Tapioca Products

Milk and Milk-based Products

- (i) Milk Powder
- (ii) Cheese
- (iii) Butter/Ghee
- (iv) Infant Food
- (v) Weaning Food
- (vi) Malted Milk Food

6. Food Packaging**7. Paper Products****8. Jute and Mesta Products****9. Cattle/Poultry/Fishery Feed Production****10. Edible Oil Processing/Vanaspathi****11. Processing of Essential Oils and Fragrances**

12. Processing and Raising of Plantation Crops

- (i) Tea, Rubber, Coffee, Coconut etc.

13. Gas based Intermediate Products

- (i) Gas exploration and Production
- (ii) Gas Distribution and Bottling
- (iii) Power Generation
- (iv) Plastics
- (v) Yarn Raw Materials
- (vi) Fertilizers
- (vii) Methanol
- (viii) Formaldehyde and FR Resin Melamine and MF Resin
- (ix) Methylamine, Hexamethylene Tetramine, Ammonium Bi-Carbonate
- (x) Nitrite Acid and Ammonium Nitrate
- (xi) Carbon Black
- (xii) Polymer Chips

14. Agro Forestry**15. Horticulture**

509 6499-3.

